

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 जून, 2017

विषय- केन्द्र सरकार के एस0पी0ए0 कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़- आंवलाघाट (रामगंगा) पंपिंग पेयजल की राज्य आकस्मिकता निधि से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 306/नियो0अनु0-धनावंटन प्रस्ताव/14 दिनांक 06 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या- 603/2012 के अनुपालन में राज्य सैक्टर (नागर) कार्यक्रम के अंतर्गत पिथौरागढ़ (आंवलाघाट रामगंगा) पंपिंग पेयजल योजना हेतु शासनादेश संख्या- 940/उन्तीस(2)/14-2(113पे0)/2012 दिनांक 22 सितम्बर, 2014 द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन रू0 7944.84 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अब तक निम्न शासनादेशों द्वारा रू0 6400.00 लाख (रू0 चौसठ करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है:-

धनराशि लाख में

क्र0सं0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	515/उन्तीस(2)/14-2(113पे0)/2012 दिनांक 26 मई, 2014	500.00
2	960/उन्तीस(2)/14-2(113पे0)/2012 दिनांक 23 सितम्बर, मई, 2014	500.00
3	560/उन्तीस(2)/14-2(113पे0)/2012 दिनांक 31 मार्च, 2015	1200.00
4	500/उन्तीस(2)/16-2(113पे0)/2012 दिनांक 19 मई, 2016	2500.00
5	51/उन्तीस(2)/16-2(113पे0)/2012 दिनांक 17 जनवरी, 2017	1500.00
6	249/उन्तीस(2)/16-2(113पे0)/2012 दिनांक 27 मार्च, 2017	200.00
	योग	6400.00

2- उपरोक्त स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत रू0 7944.84 लाख में केन्द्रांश की धनराशि रू0 7150.36 लाख एवं राज्यांश रू0 794.48 लाख के सापेक्ष एस0पी0ए0 के अंतर्गत भारत सरकार के आदेश संख्या- F.No.44(21)PFI/2013-1421 दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा रू0 1500.00 लाख एवं आदेश संख्या- F.No. 44 (21) UT /PF -1/2013-1505 दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा रू0 4839.49 लाख अर्थात् कुल रू0 6339.49 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 6400.00 लाख (केन्द्रांश रू0 5605.52 लाख एवं राज्यांश रू0 794.48 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अतः उपरोक्तानुसार योजना की कुल अनुमोदित लागत रु0 7944.84 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक अवमुक्त की गयी धनराशि रु0 6400.00 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रु0 1544.84 लाख में से वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 733.97 लाख (रु0 सात करोड़ तैतीस लाख सतानब्बे हजार मात्र) की धनराशि आकस्मिकता निधि से व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0-13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय-समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति धनराशि के समायोजन/प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर लिया जायेगा।
- (v) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (vi) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (viii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का निरीक्षण भली भाँति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- (x) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।
- (xi) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनयुल) तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (xii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/xiv-1996/2006 दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला के शासनादेशों के तहत तथा तत्परतः शासनादेशों को ही प्रयोग में लाया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि के विनियोजन के नामे डाला जायेगा, अन्ततः अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- 01- जलपूर्ति- आयोजनागत- 101- शहरी जलपूर्ति- 03- नगरीय पेयजल- 01- नगरीय पेयजल /जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण (के0स0)- 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या F 1706990022 दिनांक 16 जून, 2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 106/XXVII(2)/2017 दिनांक 25 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव

पू0सं0 03 (1)/xxvii(1)/रा0आ0क0निधि/2017 दिनांक 25 मई, 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी- प्रथम), उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0

(श्रीधर बाबू अंदोकी)

अपर सचिव

पू0सं0 882 (1)/उन्तीस(2)/17-2(113पे0)/2012 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 3-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4-बजट निदेशालय, देहरादून।
- 5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-02
- 6-मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
- 7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव